PK टाइम्स

दैनिक
लोक टुडे
जनता की आवाज...
विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 330 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | सोमवार 15 जून 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

राजस्थान के स्थानीय उद्योगों की खुली किस्मत

सरकारी टेंडरों में मिलेगा 20% तक का फायदा

वित्त विभाग की नई अधिसूचना जारी; फर्जीवाड़ा करने वाली फर्में होंगी सीधे ब्लैकलिस्ट

मनोहरसिंह खोखर। जयपुर

राजस्थान सरकार ने सरकारी खरीद में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग द्वारा 12 जून 2026 को जारी अधिसूचना (G.S.R. 18) के अनुसार अब राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा की जाने वाली खरीद और निविदाओं में स्थानीय निर्माताओं को 20% तक का 'प्राइस प्रेफरेंस' दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सीधे तौर पर करोड़ों रुपये के सरकारी ऑर्डर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नीति में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हुए SC/ST उद्यमियों के लिए 4% का विशेष कोटा भी सुरक्षित किया गया है। वहीं दूसरी ओर 'लोकल कंटेंट' का फर्जी दावा करने वाली बाहरी और कागजी कंपनियों पर नकेल कसने के लिए RTPP एक्ट के तहत ब्लैकलिस्टिंग और भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है। इस नई नीति के लागू होने से बाहरी राज्यों या विदेशी सामानों के मुकाबले राजस्थान के स्थानीय उद्योगों को सीधे तौर पर बढ़त मिलेगी।

सरकारी खरीद में 'मेक इन इंडिया' को बड़ी प्राथमिकता, स्थानीय उद्योगों को मजबूत करने और रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा नीतिगत कदम

क्या है नया 'प्राइस प्रेफरेंस' ?

नए नियमों के अनुसार, यदि कोई बाहरी या विदेशी कंपनी निविदा में सबसे कम बोली (L-1) लगाती है और राजस्थान का कोई स्थानीय निर्माता उससे 20% तक की अधिक बोली (यानी L-1 + 20% के दायरे में) लगाता है, तो स्थानीय निर्माता को भी अपनी कीमत रु1 के बराबर लाने का अवसर दिया जाएगा। कीमत बराबर करने पर कुल ऑर्डर का एक निश्चित हिस्सा या पूरा ऑर्डर स्थानीय निर्माता को सौंप दिया जाएगा।

सप्लायर्स को तीन श्रेणियों में बांटा गया -

अधिसूचना में स्थानीय सामग्री के उपयोग के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को वर्गीकृत किया गया है।
क्लास-1 लोकल सप्लायर : ऐसे निर्माता जिनके उत्पादों में स्थानीय सामग्री का हिस्सा 50% या उससे अधिक है। टेंडरों में इन्हें सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
क्लास-2 लोकल सप्लायर : ऐसे निर्माता जिनके उत्पादों में स्थानीय सामग्री 20' से अधिक लेकिन 50% से कम है। इन्हें क्लास-1 के बाद अवसर मिलेगा।
नॉन-लोकल सप्लायर : ऐसे सप्लायर जिनके उत्पादों में स्थानीय सामग्री का हिस्सा 20% से भी कम है। इन्हें प्राइस प्रेफरेंस का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की चांदी, मिलेगा 100' तक ऑर्डर -

इस नीति में राजस्थान के मूल सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई स्थानीय सूक्ष्म या लघु उद्योग तय किए गए प्राइस बैंड (L-1 + 20%) के भीतर आता है, तो उसे निविदा/ऑर्डर की कुल मात्रा का 100% तक हिस्सा आवंटित किया जा सकता है। यह कदम प्रदेश के कुटीर और छोटे उद्योगों को मंदी से उबारने और उन्हें संजीवनी देने वाला साबित होगा।

वेरिफिकेशन के नियम कड़े, धोखाधड़ी पर ब्लैकलिस्ट -

नीति का गलत फायदा उठाने वाले फर्जी सप्लायर्स पर नकेल कसने के लिए वित्त विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। टेंडर भरते समय सप्लायर को स्थानीय सामग्री के प्रतिशत का स्व-प्रमाणपत्र देना होगा। यदि टेंडर की राशि एक निश्चित सीमा से अधिक है, तो कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट ऑडिटर से प्रमाणित सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। यदि किसी कंपनी ने गलत आंकड़े देकर फायदा उठाने की कोशिश की, तो उसे नियमों के तहत ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उद्योग जगत में खुशी की लहर, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर -

सरकार के इस फैसले का राजस्थान के औद्योगिक संगठनों (जैसे FICCI, CII और FORTI) ने पूरजोर स्वागत किया है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से न केवल राजस्थान का पैसा राजस्थान के विकास में लगेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर विनिर्माण बढ़ने से युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। सरकारी टेंडरों में स्थानीय उद्योगों की भागीदारी बढ़ने से प्रदेश के राजस्व में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को मिली परमिशन

पहले पुलिस ने कर दिया था इनकार; डीसीपी ने कहा था- कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है

जयपुर

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी को विरोध-प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई है। पार्टी का 15 जून को शहीद स्मारक पर नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध-प्रदर्शन प्रस्तावित है।
पहले पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए विरोध-प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। रविवार को जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी साउथ और पार्टी प्रवक्ताओं के बीच करीब 2 घंटे तक अहम बैठक चली, इसके बाद पुलिस ने इसकी अनुमति जारी की।
सोमवार दोपहर करीब 3 बजे से गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित शहीद स्मारक पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके भी जयपुर पहुंचेंगे।
CJP के फाउंडर ने युवाओं से की अपील अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर लोगों से 15 जून को जयपुर के शहीद स्मारक पहुंचने की अपील की। दीपके ने कहा कि नीट पेपर लीक के कारण राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है।
अब वक्त है एकजुट होकर अपनी आवाज रखने का। आप जरूर आइएगा। मिलकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी और जयपुर के शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन होगा।

जसपाल राणा की अर्थी को पंकज सिंह ने दिया कंधा

वाराणसी

इंटरनेशनल शूटर जसपाल राणा का शनिवार को काशी में अंतिम संस्कार किया गया। बेटे युवराज (21) ने मणिकर्णिका घाट पर पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे विधायक पंकज सिंह और नीरज सिंह ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। दरअसल, पंकज सिंह, जसपाल राणा के बहनोई हैं। पार्थिव शरीर को गंगा स्नान कराने के बाद गारद ने उन्हें अंतिम सलामी दी। शनिवार दोपहर करीब 3:52 बजे चार्टर विमान से जसपाल राणा का पार्थिव शरीर देहरादून से वाराणसी एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल भवन स्थित एयर कार्गो परिसर में जसपाल राणा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंकज सिंह दोपहर करीब 12:15 बजे ही वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच गए थे।

100 प्रतिशत इथेनॉल ईंधन को मिली कानूनी मंजूरी, विदेशी तेल पर निर्भरता घटाने की दिशा में बड़ा कदम

नई दिल्ली।

देश के ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शत-प्रतिशत इथेनॉल ईंधन को कानूनी मान्यता देने से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस निर्णय के बाद भविष्य में पूरी तरह इथेनॉल से चलने वाले वाहन भारतीय सड़कों पर वैधानिक रूप से संचालित किए जा सकेंगे। इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

बीते एक दशक में टेक्नोलॉजी अपनाने वाले देश से टेक प्रोवाइडर के रूप में उभरा भारत: नरेंद्र मोदी

नीस।

भारत बीते एक दशक में टेक्नोलॉजी अपनाने वाले देश से एक टेक प्रोवाइडर के रूप में उभरा है और देश से निकलने वाले समाधान और इनोवेशन में मानवता के एक बड़े हिस्से को लाभ पहुंचाने की क्षमता है। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिया। फ्रांस के नीस शहर में हो रही 'भारत इनोवेट्स समिट' के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'एक दशक पहले, दुनिया भारत को मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी अपनाने वाले देश के तौर पर देखती थी, लेकिन आज भारत तेजी से टेक्नोलॉजी देने वाले देश के रूप में उभर रहा है। भारत से निकले इनोवेशन और समाधानों में मानवता के एक बड़े हिस्से को फायदा पहुंचाने की क्षमता है। 'भारत इनोवेट्स' इसी सोच को आगे बढ़ाता है और यह दुनिया के लिए एक निमंत्रण है कि वे भारत के साथ मिलकर काम करें और ग्लोबल इनोवेशन के अगले अध्याय को साथ मिलकर तैयार करें।'
उन्होंने आगे कहा कि इनोवेशन भारत के डीएनए में समाहित है। हजारों सालों से भारत ने अपनी खोजों और ज्ञान से दुनिया का मार्गदर्शन किया है। गणित से लेकर खगोल विज्ञान तक, और चिकित्सा से लेकर योग तक, भारत का योगदान पूरी मानवता के लिए आधारभूत रहा है। आज हम इसी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और इसे नई दिशा व गति दे रहे हैं।
मानवता को भारत की प्राथमिकता बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मानवता की सेवा करे। इसी सिद्धांत ने हमारे डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाया है और यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार है।
आगे कहा कि हमारा विजन 'एआई फॉर ऑल' (सभी के लिए एआई) के सिद्धांत पर आधारित है, जो हर व्यक्ति की भलाई और खुशी के लिए समर्पित है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में 12 वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव, करोड़ों लोगों को मिला लाभ: भजनलाल शर्मा

जयपुर।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए व्यापक बदलावों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को जन-केंद्रित बनाने और आम नागरिकों तक सुलभ उपचार पहुंचाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि सरकार ने उपचार को अधिकार, दवाओं को सुलभ और स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन के अनुकूल बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिससे करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्रों का विस्तार, नए एम्स संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, डिजिटल हेल्थ मिशन तथा स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण जैसी योजनाओं ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा दी है।
मुख्यमंत्री के अनुसार इन दूरदर्शी पहलों के चलते स्वास्थ्य सेवाएं अब पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और प्रभावी हो गई हैं। इससे करोड़ों परिवारों को बेहतर इलाज, आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति विश्वास मिला है।
उन्होंने कहा कि 'नए भारत' की यह स्वस्थ यात्रा देश को 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ा रही है और स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे सुधार भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं।

जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई : कर्नाटक पुलिस के तीन कर्मी 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक पुलिस के तीन कर्मियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसीबी जयपुर नगर-प्रथम इकाई द्वारा मुख्यालय के निर्देश पर की गई। गिरफ्तार आरोपियों में बेंगलुरु के एच.ए.एल. थाने की उप निरीक्षक अनीथा के., हेड कांस्टेबल उलवप्पा और हेड कांस्टेबल यतीश शामिल हैं। एसीबी टीम ने उलवप्पा को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही दबोच लिया, जबकि बाद में पूछताछ के आधार पर अन्य दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। 2 लाख रुपए की मांग का मामला
एसीबी को मिली शिकायत में परिवादी ने बताया कि उसकी पुत्रवधु द्वारा दहेज उत्पीड़न का मामला बेंगलुरु के एच.ए.एल. थाने में दर्ज कराया गया था। उसी केस की जांच के सिलसिले में कर्नाटक पुलिस की टीम जयपुर आई थी। आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने केस को कमजोर करने और परिवार को राहत देने के बदले 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। शिकायत के बाद एसीबी ने सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगना सही पाया गया। एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई करते हुए जयपुर के एक होटल में जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी ने 40 हजार रुपए की पहली किस्त ली, टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया।

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच आगे बढ़ रहा भारत, विकास दर दुनिया में सबसे तेज: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

बेंगलुरु। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के 'विकसित भारत' कार्यक्रम में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह केंद्र सरकार नहीं है, जो कि दावा कर रही है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, बल्कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े स्वयं इसी ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत को दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था मानता है।
विपक्षी नेता राहुल गांधी के बयान पर सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस नेता देश के आर्थिक प्रदर्शन की लगातार आलोचना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, हर तिमाही और हर साल भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार कहते रहते हैं कि कोई बड़ी आर्थिक आपदा आने वाली है, लेकिन भारत के लिए ऐसी कोई आपदा नहीं आने वाली है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता की बार-बार की आलोचना से देश की आर्थिक स्थिति के बारे में नागरिकों के मन में गलत धारणा बन सकती है।

बेकार समझा जाने वाला कैक्टस बना किसानों का 'ब्लू गोल्ड'

मेक्सिको में 1.4 लाख करोड़ रुपए की टकीला इंडस्ट्री, इसके लिए कच्चा माल भेज रहे भारतीय किसान

हैदराबाद

भारत में एक कांटेदार रेगिस्तानी पौधे ने नई ड्रिंक्स इंडस्ट्री को जन्म दे दिया है। आंध्र प्रदेश के कांदुकुर में ज्यादातर किसान पहले टमाटर, मूंगफली और मक्का उगाते थे। 2010 में कुछ व्यापारी एगेव अमेरिकाना नाम के कैक्टस की तलाश में कांदुकुर पहुंचे। इसे किसान बेकार समझकर खेत की बाड़ के रूप में लगाते थे। बीबीसी वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, यही एगेव कैक्टस मेक्सिको की 1.4 लाख करोड़ रुपए की टकीला और मेजकल इंडस्ट्री की रीढ़ है।
मेक्सिको के जलिस्को राज्य में सिर्फ चुनी हुई जगहों पर उगने वाला 'ब्लू एगेव' टकीला बनाने के लिए मान्य है। भारत में अभी इसकी कमर्शियल खेती नहीं होती। किसान और उद्यमी जंगली एगेव इकट्ठा

करते हैं। कांदुकुर में अब 100 किमी के दायरे में कई गांवों के किसान डिस्टिलरीज को बड़े पैमाने पर सप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें अच्छी कीमत मिलती है। इसीलिए इसे 'ब्लू गोल्ड' कहा जाने लगा है।
एगेव की खेती मुश्किल है। पौधे का सबसे अहम हिस्सा 'पीना' (अनानास जैसा दिखने वाला कोर) होता है, जिसमें शुगर जमा होती है, लेकिन जैसे ही पौधा फूल देने लगता है, सारी शुगर तेजी से ऊपर तने की ओर चली जाती है और पीना बेकार हो जाता है। किसानों के मुताबिक, पौधे को फूल आने से ठीक पहले काटना पड़ता है। काटने के बाद 24 घंटे के भीतर इसे प्रेशर कुकर तक पहुंचाना जरूरी है, वरना शुगर सड़ने लगती है। स्वाद खराब हो जाता है।
भारत में एगेव स्पिरिट का बाजार सालाना 31' बढ़ रहा है। अब उपभोक्ता नए स्पिरिट्स आजमाने के लिए ज्यादा खुले हैं, हालांकि एगेव ड्रिंक्स व्हिस्की की जगह नहीं ले सकतीं, लेकिन यह अपना अलग बाजार बना सकती हैं। 2011 में भारत की पहली एगेव डिस्टिलरी शुरू करने वाले डेसमंड नजारेथ सैटेलाइट इमेजरी की मदद से इसकी खेती के लिए जमीन तलाश रहे हैं। एक बार गलत जगह लगाने पर 9-13 साल की मेहनत बेकार हो सकती है। हालांकि भारत और मेक्सिको के मॉडल में बड़ा फर्क है। मेक्सिको में दशकों की सेलेक्टिव ब्रीडिंग से एगेव की क्वालिटी एक जैसी है, जबकि भारत में शुगर की मात्रा अलग-अलग है। इससे प्रोडक्शन स्टैंडर्डाइज करना मुश्किल है। यही वजह है कि 'लोका लोका' जैसे ब्रांड अब भी मैक्सिको से ब्लू एगेव मंगाते हैं। मेक्सिको में जलिस्को राज्य की लाल मिट्टी में वर्षों से एगेव की व्यवस्थित खेती होती है। भारत में अभी एगेव की संगठित खेती नहीं होती। कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में बिखरे जंगली पौधों को स्थानीय एजेंट इकट्ठा करते हैं। डेक्कन पठार के लाखों एकड़ उपयुक्त जमीन के साथ भारत भविष्य में मेक्सिको को टक्कर दे सकता है।

सम्पादकीय

"मानवता सुख शांति प्रेम का, अखिल विश्व में हो
विस्तारस्वतंत्रता का हनन न होवे, रहे सुरक्षित जन अधिकार"

पश्चिम एशिया के युद्ध में तटस्थ देशों के जहाजों पर हमले

अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी

पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजराइल के युद्ध की आग की चपेट में अब वैसे देश और लोग भी आने शुरू हो चुके हैं, जो पूरी तरह तटस्थ हैं और वे सिर्फ जरूरी आपूर्ति सुनिश्चित करने की उम्मीद में उस क्षेत्र में मौजूद हैं। कायदे से आम लोगों की जरूरतों के मद्देनजर अपनी ड्यूटी करने वाले अन्य देशों के लोगों को किसी भी पक्ष की ओर से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन हाल में अमेरिका ने इस मामले में जिस स्तर की लापरवाही और मनमानी दिखाई है, उससे यही लगता है कि उसे सामान्य स्थिति के बहाल होने की कोई फिक्र नहीं है। वरना क्या वजह है कि पिछले तीन-चार दिनों के भीतर उसने उस क्षेत्र में मौजूद तीन भारतीय जहाजों को निशाना बनाया। उसे यह समझना क्यों जरूरी नहीं लगा कि वह जिन जहाजों पर हमला कर रहा है, वे वाणिज्यिक हैं और किसी भी रूप में इस युद्ध का हिस्सा नहीं हैं? गौरतलब है कि ओमान तट के पास एक वाणिज्यिक जहाज 'सेट्टेबेलो' पर अमेरिका की ओर से किए गए एक हमले में तीन भारतीय नाविकों की जान चली गई। जहाज पर चौबीस लोग सवार थे, जिनमें से इक्कीस को किसी तरह बचा लिया गया। इससे पहले सोमवार को मारिवेक्स नाम के तेल टैंकर पर भी हमला किया गया था, जिसके बाद भारतीय नाविकों ने मदद के लिए आपात संदेश भेजा था। अब गुरुवार को ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक जहाज एमटी जलवीर पर भी हमला किया गया। हालांकि इन दोनों घटनाओं में सभी नाविकों को बचा लिया गया। सवाल है कि अमेरिका के लिए यह समझना मुश्किल क्यों हो रहा है कि ईरान के साथ जारी उसके युद्ध के क्रम में अगर तटस्थ देशों के वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाता है, तो अन्य मोर्चों पर कैसी जटिल स्थिति खड़ी हो सकती है। दुनिया के कई देश पहले ही गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। जिन वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया गया, वे किसी भी रूप में युद्ध का हिस्सा नहीं थे। मगर बिना किसी मजबूत आधार या उकसावे के अमेरिका ने हमला किया। शायद उसे अब यह सोचने की जरूरत है कि उसके रवैये और जिद का हासिल क्या सामने आ रहा है। यह बेवजह नहीं है कि भारत ने हमले और उसमें नाविकों के मारे जाने पर अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब कर अपनी तीखी आपत्ति दर्ज की। विदेश मंत्रालय ने मध्य-पूर्व में संवेदनशील सुरक्षा हालात पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए समुद्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले को भू-राजनीतिक शत्रुता का नतीजा बताया। एक ओर ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को बाधित किया हुआ है, तो दूसरी ओर अमेरिका ने उस समूचे इलाके में नाकेबंदी कर रखी है। आखिर क्या वजह है कि भारत या किसी देश के वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने में भी उसे कोई हिचक नहीं हो रही है? होर्मुज या अन्य समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवाजाही बहाल किया जाना इसलिए भी जरूरी है कि सिर्फ उसकी वजह से दुनिया के कई देशों में ऊर्जा और तेल की आपूर्ति बुरी तरह बाधित है और इसका विपरीत असर बड़े दायरे में जनजीवन पर पड़ रहा है। विडंबना यह है कि जहां युद्ध के बावजूद वाणिज्यिक जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार किया जाना चाहिए था, वहीं बिना किसी आधार के इन जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं। सवाल है कि वर्चस्व की जंग के बीच अमेरिका की नजर में क्या अंतरराष्ट्रीय कानूनों की कोई अहमियत रह गई है?

> "दुनिया के कई देश पहले ही गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। जिन वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया गया, वे किसी भी रूप में युद्ध का हिस्सा नहीं थे।

निशानेबाजी के अग्रदूत जसपाल राणा, एक स्वर्णिम गाथा

निशानेबाजी को भारत के सबसे सफल ओलंपिक खेलों में से एक बनाने की नींव जिन कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों ने रखी, उनमें जसपाल राणा का नाम सबसे ऊपर आता है। 90 के दशक में, जब भारतीय खेल परिदृश्य पर मुख्य रूप से क्रिकेट का बोलबाला था, तब उत्तराखंड के इस युवा निशानेबाज ने अपनी सटीक एकाग्रता और अचूक निशानों से देश में एक नई खेल क्रांति का सूत्रपात किया। पिस्तौल स्पर्धाओं में उनके असाधारण प्रदर्शन ने न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तिरंगे का मान बढ़ाया, बल्कि देश के युवाओं को यह विश्वास भी दिलाया कि भारत निशानेबाजी में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है।

प्रारंभिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि और संघर्ष के दिन

जसपाल राणा का जन्म 28 जून 1976 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के चिल्ला गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता, नारायण सिंह राणा, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में एक अधिकारी थे। पिता के सैन्य और सुरक्षा बलों से जुड़े होने के कारण घर में हमेशा अनुशासन और हथियारों के प्रति एक स्वाभाविक सम्मान का माहौल था। जसपाल का बचपन देहरादून की वादियों और बाद में दिल्ली में बीता, जहाँ उनके पिता ही उनके पहले कोच, मार्गदर्शक और सबसे बड़े आलोचक बने। उस दौर में भारत में निशानेबाजी एक बेहद महंगा और आम पहुंच से दूर का खेल माना जाता था। आधुनिक शूटिंग रेंज की कमी, हथियारों के आयात में प्रशासनिक बाधाएं और कारतूसों की सीमित उपलब्धता जैसी कई गंभीर चुनौतियां थीं। इन सबके बावजूद, नारायण सिंह राणा ने जसपाल और उनके भाई-बहनों को इस खेल में आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जमा-पूंजी लगा दी। जसपाल ने मात्र 12 वर्ष की आयु में 1988 में अपनी पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने सफर की शुरुआत कर दी थी।

खेल करियर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक सफलताएं

जसपाल मुख्य रूप से 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल, रैपिड फायर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं के विशेषज्ञ रहे हैं। उनका पूरा करियर देश-विदेश में पदकों और रिकॉर्ड्स से भरा रहा है। जसपाल राणा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बड़ी कामयाबी 1994 में इटली के मिलान में आयोजित विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में मिली। उन्होंने जूनियर वर्ग की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में न केवल स्वर्ण पदक जीता, बल्कि 588/600 का स्कोर बनाकर तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी की। इस एक पदक ने भारतीय खेल जगत का ध्यान उनकी ओर खींचा। इसके बाद एशियाई खेलों में जसपाल राणा का प्रदर्शन हमेशा से भारतीय खेल इतिहास के सुनहरे अध्यायों में गिना गया। 1994 के हिरोशिमा एशियाई खेलों में मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने पुरुषों के 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल एकल में स्वर्ण पदक जीतकर धमाका कर दिया। इसके बाद 1998 (बैंकॉक) और 2002 (बुसान) के खेलों में उन्होंने टीम और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में रजत और कांस्य पदक जीते। 2006 का दोहा एशियाई खेल उनके करियर का सबसे यादगार और भावुक कर देने वाला टूर्नामेंट था। खेल विश्लेषक मान चुके थे कि राणा का सर्वश्रेष्ठ समय बीत चुका है, लेकिन उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब दिया। गंभीर शारीरिक दर्द और तेज बुखार के बावजूद उन्होंने 3 स्वर्ण पदक (25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल एकल, टीम और 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल) जीते। सेंटर फायर पिस्टल में उन्होंने 589/600 का स्कोर बनाकर एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके साथ ही, राष्ट्रमंडल खेलों में भी जसपाल राणा का एकछत्र राज रहा। उन्होंने 1994 से 2006 के बीच इन खेलों में 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 15 पदक अपने नाम किए और समरेश जंग व गगन नारंग के साथ मिलकर भारतीय निशानेबाजी का दबदबा कायम किया।

मुख खेल पुरस्कार और राष्ट्रीय सम्मान

जसपाल राणा की असाधारण खेल उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक और खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। हिरोशिमा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्हें 1994 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। इसके ठीक अगले वर्ष, 1995 में बहुत कम उम्र में खेल क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया। बाद के वर्षों में, बतौर कोच देश के सर्वश्रेष्ठ निशानेबाजों को तैयार करने के लिए उन्हें 2020 में खेल कोचिंग के सर्वोच्च सम्मान द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

बतौर कोच 'दूसरी पारी' और चैंपियन मेकर की भूमिका

सक्रिय निशानेबाजी से संन्यास लेने के बाद जसपाल राणा ने खेल को अलविदा नहीं कहा, बल्कि वे नई पीढ़ी को तराशने के काम में जुट गए। उन्होंने देहरादून में जसपाल राणा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की, ताकि उत्तराखंड और देश के अन्य हिस्सों के ग्रामीण युवाओं को खेल और शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकें। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय जूनियर और सीनियर पिस्तौल टीम के मुख्य कोच के रूप में जिम्मेदारी संभाली। जसपाल राणा को एक बेहद सख्त, अनुशासित और तकनीकी रूप से निपुण कोच माना जाता है। उनकी कोचिंग की सबसे शानदार बानगी स्टार निशानेबाज मनु भाकर हैं, जिन्हें विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनाने और उनकी तकनीक को धार देने में जसपाल राणा का सबसे बड़ा योगदान रहा है। मनु के अलावा सौरभ चौधरी, अनीश भानवाला, चिंकी यादव और अभिषेक वर्मा जैसे शीर्ष निशानेबाजों ने जसपाल राणा के मार्गदर्शन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईएसएसएफ विश्व कप और चैंपियनशिप में दर्जनों स्वर्ण पदक जीते।

कानूनों का दुरुपयोग रोकने का समय

डॉ. ऋतु सारस्वत

हाल में देश की शीर्ष अदालत ने एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए एक ऐसी चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो केवल न्याय व्यवस्था ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। न्यायालय ने कहा, वैवाहिक अथवा व्यावसायिक संबंधों में जुड़े पक्षकार प्रतिशोध की भावना से एक-दूसरे के विरुद्ध आपराधिक प्रकृति के तुच्छ एवं दुर्भावनापूर्ण दावे करने तथा आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। वे अनैतिक और कुटिल उपायों का सहारा लेते हैं। अनेक मामलों में कानून और पुलिस का सहारा न्याय प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे पक्षकार तथा उसके परिवारजनों पर दबाव बनाने, उन्हें परेशान करने तथा प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से लिया जाता है। यह सब पक्षकार और उसके परिवारजनों के प्रति घृणा और तिरस्कार की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की यह चिंता निराधार नहीं है।

वैवाहिक विवादों में झूठे और दुर्भावनापूर्ण मुकदमों की प्रवृत्ति को लेकर समय-समय पर न्यायालयों ने गंभीर टिप्पणियां की हैं।

दहेज उत्पीड़न, वैवाहिक क्रूरता, घरेलू हिंसा तथा अन्य कानूनी प्रविधानों के अंतर्गत ऐसे मामले तमाम सामने आए हैं, जिनमें आरोप न्यायिक परीक्षण में सिद्ध नहीं हो सके। कई बार सामान्य, अस्पष्ट और व्यापक आरोपों के आधार पर पूरे परिवार को मुकदमेबाजी के दायरे में खड़ा कर दिया जाता है। यह सच है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा, दहेज उत्पीड़न और भेदभाव की समस्या वास्तविक है तथा उससे संघर्ष करना किसी भी सभ्य समाज का दायित्व है, किंतु भारतीय समाज की चुनौती केवल इतनी भर नहीं है। सत्य यह भी है कि अनेक पुरुष झूठे आरोपों, दुर्भावनापूर्ण मुकदमों और लंबी न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण मानसिक, सामाजिक और आर्थिक पीड़ा का सामना कर रहे हैं। पुरुषों की समस्याएं आज भी अपेक्षित सामाजिक और विधिक विमर्श का विषय नहीं बन सकी हैं। परिणामस्वरूप अनेक बार उनकी पीड़ा को या तो गंभीरता से लिया ही नहीं जाता अथवा उसे सामाजिक विमर्श का वैध विषय नहीं माना जाता। यही कारण है कि 22 जनवरी, 2025 को 'ज्योति उर्फ किट्टू बनाम राज्य' मामले में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि यह धारणा कि वैवाहिक संबंधों में केवल महिलाएं ही शारीरिक अथवा मानसिक क्रूरता की शिकार होती हैं और इसके कोई अपवाद नहीं हैं, जीवन की कठोर वास्तविकताओं के विपरीत हो सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, जिस प्रकार महिलाएं क्रूरता और हिंसा से संरक्षण की अधिकारिणी हैं, उसी प्रकार पुरुष भी विधि के अंतर्गत समान सुरक्षा पाने के अधिकारी हैं। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि कोई भी महिला अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान को दांव पर लगाकर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न की मिथ्या शिकायत नहीं करेगी। यही कारण था कि ऐसे आरोपों को सामान्यत: विश्वसनीयता के साथ देखा जाता था। इस संदर्भ में गत वर्ष केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि बदलते सामाजिक परिदृश्य में इस धारणा का यांत्रिक रूप से अनुसरण नहीं किया जा सकता कि केवल आरोप लगाए जाने मात्र से उसकी सत्यता स्वत: सिद्ध हो जाती है। न्यायालय ने माना कि यद्यपि ऐसे मामले अपवादस्वरूप हो सकते हैं, तथापि कुछ प्रकरणों में गंभीर आरोप प्रतिशोध, दबाव या अन्य स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से भी लगाए गए। इसलिए किसी भी आरोप की सत्यता का निर्धारण पूर्वधारणाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों और साक्ष्यों की कसौटी पर ही किया जाना चाहिए। वास्तव में समस्या का मूल कारण अधिकार नहीं, बल्कि अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच बिगड़ता संतुलन है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है, किंतु उतना ही आवश्यक यह भी है कि उन अधिकारों के प्रयोग के साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित हो। जब किसी कानून का उपयोग संरक्षण के स्थान पर प्रतिशोध, दबाव अथवा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति का माध्यम बनने लगे, तो उसका प्रभाव केवल संबंधित पक्षों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है। देशभर में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं, जिनमें वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के पश्चात आरोप असत्य अथवा प्रमाणित न हो पाने वाले सिद्ध हुए। ऐसे मामलों में केवल मुकदमे का परिणाम ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि वह सामाजिक, मानसिक और आर्थिक क्षति भी महत्वपूर्ण होती है, जिसका सामना आरोपित व्यक्ति और उसका परिवार करते हैं। प्रतिष्ठा की हानि, सामाजिक कलंक, पारिवारिक विघटन और मानसिक आघात ऐसे घाव हैं, जिनकी भरपाई प्राय: किसी न्यायिक आदेश से नहीं हो पाती। यह भी उतना ही सत्य है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली वास्तविक हिंसा और उत्पीड़न के मामलों में कानून का कठोर और प्रभावी होना अनिवार्य है, किंतु किसी एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या की उपेक्षा करके नहीं किया जा सकता। एक ओर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाज के लिए चुनौती है, तो दूसरी ओर झूठे आरोपों और विधिक प्रक्रियाओं के दुरुपयोग की समस्या भी न्याय व्यवस्था के समक्ष एक गंभीर प्रश्न बनकर उभरी है। इसका समाधान अब होना ही चाहिए।

> एक ओर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाज के लिए चुनौती है, तो दूसरी ओर झूठे आरोपों और विधिक प्रक्रियाओं के दुरुपयोग की समस्या भी न्याय व्यवस्था के समक्ष एक गंभीर प्रश्न बनकर उभरी है। इसका समाधान अब होना ही चाहिए।

कैसे रुकेगी जादू-टोने के भ्रम वाली हिंसा

जिस दौर में देश की अर्थव्यवस्था की चमकती तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जा रही हो, उसी बीच आए दिन जब महज अंधविश्वास की वजह से निर्दोष लोगों की हत्या की घटनाएं भी हो रही हों, तो यह अपने आप में विकास की मौजूदा परिभाषा पर एक सवालिया निशान है। कुछ दिन पहले ओड़िशा के संबलपुर जिले में साठ साल की एक महिला और उसकी बेटी की सिर्फ इसलिए कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई कि उन पर कुछ लोगों को जादू-टोना करने का संदेह था। यह कोई पहली या अकेली घटना नहीं है, जिसमें सिर्फ अंधविश्वास के कारण निर्दोष महिलाओं की हत्या कर दी गई। झारखंड और ओड़िशा सहित देश के अन्य इलाकों से भी डायन या जादू-टोना के अंधविश्वास की वजह से आदिवासी या कमजोर तबकों की महिलाओं को यातना देने से लेकर उनकी हत्या कर देने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। सरकारें मौजूदा कानूनी प्रक्रिया के तहत हत्या के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, लेकिन उसका असर इतना नगण्य है कि कुछ दिनों बाद फिर डायन या जादू-टोना के नाम पर हत्या की कोई अन्य घटना सामने आ जाती है। यह सोचने की जरूरत है कि विकास के दावों के बीच अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं। विकास की चकाचौंध के पीछे भारतीय समाज की इस स्याह तस्वीर को हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं। एक तरफ हम आधुनिकता के दंभ में जीते हैं, तो दूसरी तरफ समाज का एक वर्ग ऐसा भी है, जिसमें मनुष्यता का बोध नहीं। वह बेगुनाह लोगों की हत्या होते देखता है। दूसरी ओर, यह समझना मुश्किल है कि देश के दूरदराज इलाकों में सरकारें आधुनिक तकनीकी संसाधन और सुविधाएं पहुंचाने में कोई कोताही नहीं करतीं, लेकिन लोगों के बीच ऐसी सामान्य चेतना और समझ का विस्तार नहीं कर पातीं कि जादू-टोना और डायन जैसी धारणाएं महज अंधविश्वास हैं और यह किसी भी समाज के पिछड़े रह जाने के सबसे बड़े कारकों में से एक हैं। विडंबना यह है कि ऐसी घटनाओं को सामान्य आपराधिक घटनाओं की तरह देखा जाता है और उसके पीछे सामाजिक जड़ता और मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को समझने और उसी मुताबिक उसका दूरगामी हल निकालने की कोशिश नहीं की जाती। यह भी पढ़ें: वैज्ञानिक दौर में भी तेजी से पांव पसार रहा अंधविश्वास, तंत्र मंत्र के नाम पर खूब होता है अपराध आज के वैज्ञानिक दौर में भी समाज में अंधविश्वास की जड़ें इतने गहरे तक फैली हुई हैं कि कई बार लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। कर्म और तर्क के सिद्धांत को कोने में रखकर कुछ लोग तंत्र-मंत्र और जादू-टोना का सहारा लेते हैं, जिसके अक्सर भयावह परिणाम सामने आते हैं। कभी तांत्रिक अनुष्ठान में किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, तो कभी डायन कहकर सार्वजनिक तौर पर प्रताड़ना की हदें पार कर दी जाती हैं।

सरकारी स्कूल से टूटता भरोसा

शरद दाधीच
वरिष्ठ पत्रकार

सरकारी स्कूलों में नामांकन नहीं बढ़ पा रहा। पिछले चार साल में नौ लाख से अधिक विद्यार्थी कम हो गए। सरकार की तमाम योजनाएँ नामांकन बढ़ाने में फ्लॉप साबित हो रही हैं।

सरकार नवाचार कर नामांकन बढ़ाने की जुगत में है पर कई कारणों से यह सफल नहीं हो पा रहा। बार-बार अदालत की फटकार या बैठकों में लिए जा रहे निर्णय के अनुकूल व्यवस्था ही नहीं हो पा रही। विडंबना यह भी है कि शिक्षा के अधिकार कानून के बावजूद कई विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएँ तक नहीं हैं। पिछले साल कुछ स्कूलों की छत अथवा दीवार गिरने के बाद उच्च न्यायालय की दखल के बाद मरम्मत का कार्य भी फेल रहा। मरम्मत के नाम पर भी सिर्फ रंग-रोगन कर सरकार को ही चूना लगा दिया गया। डीडवाना-कुचामन ही नहीं नागौर समेत अन्य जिलों में यह गड़बड़ी पकड़ी गई। सरकार की ओर से सुधार के लिए कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं। वर्ष 2025-26 के बजट में 174 करोड़ से अधिक की राशि 2000 स्कूलों की मरम्मत के लिए स्वीकृत की गई है। इसके अलावा 1680 नए स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। बावजूद इसके कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। हर बार की तरह सरकार की ओर से इस बार भी नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। शिक्षकों को गांव-ढाणी जाकर बच्चों और अभिभावकों से संपर्क करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कई जगह रैलियां निकाली जाएंगी तो सभी स्कूलों में प्रवेशोत्सव के तहत लोगों का ध्यान खींचा जा रहा है। साथ ही सरकारी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। मुफ्त पाठ्यपुस्तक,

यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन और बालिकाओं के लिए विशेष योजनाओं को भी आकर्षण के रूप में पेश किया जा रहा है, सो अलग। सरकारी स्कूलों की बदहाल आधारभूत सुविधाएं भी एक बड़ा कारण हैं। आज भी कई विद्यालय जर्जर भवनों, टूटे फर्नीचर, खराब शौचालयों और पेयजल संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई जगह बच्चों को पेड़ों के नीचे या असुरक्षित कमरों में पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे हालात देखकर अभिभावकों का चिंतित होना स्वाभाविक है। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम और आधुनिक शिक्षा की बढ़ती मांग ने भी सरकारी स्कूलों की चुनौती बढ़ाई है। निजी स्कूल तकनीक, स्मार्ट क्लास, गतिविधियों और अंग्रेजी शिक्षा को बड़े आकर्षण के रूप में पेश करते हैं, जबकि अधिकांश सरकारी स्कूल अभी भी संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। बदलते समय के साथ शिक्षा व्यवस्था में जिस तेजी से सुधार होना चाहिए था, वह नजर नहीं आता।

बावजूद इसके फिलहाल इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा। अभिभावक अब केवल मुफ्त सुविधाओं के आधार पर स्कूल नहीं चुन रहे, वे अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। जब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, जर्जर भवन, अंग्रेजी माध्यम की सीमित व्यवस्था, तकनीकी संसाधनों का अभाव और पढ़ाई की कमजोर गुणवत्ता जैसी समस्याएं सामने आती हैं, तब लोग निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं।

फिर भड़का युद्ध

अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध छिड़ने के कारण न केवल पश्चिम एशिया का संकट और गहरा गया है, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भी समस्याएं बढ़ गई हैं। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने जिस तरह होर्मुज समुद्री जल मार्ग को फिर से बंद करने का फैसला किया, उसके बाद अमेरिका और उसके बीच तनाव तो बढ़ेगा ही, खाड़ी के देशों से होने वाली तेल और गैस की आपूर्ति के भी बिल्कुल ठप होने का अंदेशा है। इसके चलते पहले से ही चढ़े तेल एवं गैस के मूल्य और बढ़ सकते हैं। इससे भारत समेत अन्य देशों और विशेष रूप से एशियाई देशों का संकट और बढ़ेगा। इससे खराब बात और कोई नहीं कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की जो थोड़ी-बहुत गुंजाइश बन रही थी, वह भी समाप्त होती दिख रही है। इसके लिए दोनों ही पक्षों का अड़ियल रवैया जिम्मेदार है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यह चाहते हैं कि ईरान उनके मन मुताबिक समझौता करे, वहीं ईरानी नेतृत्व न तो परमाणु हथियार बनाने के अपने इरादे का परित्याग करने को तैयार है और न ही होर्मुज पर अपना दावा छोड़ने के लिए। वह इजरायल के लिए खतरा बने हिजबुल्ला को समर्थन देने से पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं। वह यह तो चाहता है कि इजरायल लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला करने से बाज आए, लेकिन वह इस संगठन को इजरायल को निशाना बनाने से रोकने के लिए तैयार नहीं। समस्या केवल यह नहीं कि ईरान होर्मुज पर अवैध कब्जा करना चाहता है, बल्कि यह भी है कि अमेरिकी सेना उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी के चलते इस समुद्री जल मार्ग से इस बहाने जहाजों को नहीं निकलने दे रहा है कि वे या तो ईरान जा रहे थे या फिर वहां से आ रहे थे। इसी को आधार पर बनाकर उसने पिछले चार दिनों में तीन जहाजों पर हमले किए। इनमें से दो पलाऊ और एक गिनी-बिसाऊ का था, लेकिन इन तीनों में भारतीय नाविक सवार थे। इनमें से एक जहाज पर अमेरिकी हमला घातक साबित हुआ। इस हमले में तीन भारतीय नाविक मारे गए। साफ है कि अमेरिकी सेना निहायत ही गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रही है। वह जहाजों को रोकने, जब्त करने के बजाय जिस तरह उन्हें ध्वस्त करने का काम कर रही है, वह अस्वीकार्य और अक्षम्य है। यह सर्वथा उचित है कि भारत ने अपने तीन भारतीय नाविकों के मारे जाने की घटना पर अमेरिकी राजनयिक को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं।

शगुन शर्मा

'खतरों के खिलाड़ी 15' में दिखेंगी बोलीं- ऊंचाई से लगता है सबसे ज्यादा डर; शो में ओरी के साथ BTS वीडियो जरूर बनाऊंगी

टीवी एक्ट्रेस शगुन शर्मा अब रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आने वाली हैं। बातचीत में शगुन ने अपने सबसे बड़े डर, मुंबई आने के संघर्ष, मानसिक मजबूती और 'खतरों के खिलाड़ी' को लेकर अपनी तैयारी पर बात की।

आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है?
मुझे सबसे ज्यादा डर हाइट्स से लगता है। जब भी मैं बहुत ऊंचाई पर जाती हूं, तो मैं कांपने लगती हूं। कई बार तो फ्रीज भी हो जाती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह शो उस डर को हराने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।

उस डर को कैसे ओवरकम करेंगी?
जवाबः मैं खुद को यही समझाऊंगी कि मैं सुरक्षित हूं। शो के दौरान पूरी सेफ्टी होती है। असली डर यही होता है कि कहीं गिर न जाएं या कुछ हो न जाए। अगर मैं अपने दिमाग से वो डर निकाल पाई, तो शायद अच्छा कर पाऊंगी।

आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क क्या था?
मुंबई आकर एक्टिंग करना। मैं हिमाचल प्रदेश से हूं। पढ़ाई छोड़कर इस इंडस्ट्री में आना, जहां मैं किसी को नहीं जानती थी, मेरे परिवार का भी यहां कोई कनेक्शन नहीं था। मेरे लिए वो बहुत बड़ा रिस्क था।

मुंबई आने के बाद सबसे बड़ा कल्चर शॉक क्या था?
हिमाचल से मुंबई आना बहुत बड़ा कल्चर शॉक था। वहां से आने वाले लोगों को यहां की कई चीजें बहुत अलग लगती ह ै , ले कि न मैंने यहां कॉलेज किया, इसलिए धीरे-धीरे मैं मुंबई की लाइफस्टाइल में कम्फर्टेबल हो गई।

इस बार पुराने और नए कंटेस्टेंट्स साथ होंगे। क्या इसे लेकर एक्साइटमेंट है?
शायद इसलिए इस बार थीम 'डर का नया दौर' रखी गई है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुराने और नए कंटेस्टेंट्स साथ आए हों, लेकिन मैं पहले से कोई डर अपने दिमाग में नहीं रखना चाहती क्योंकि अगर मैं पहले से सोचूंगी, तो खुद को और ज्यादा डरा दूंगी।

इस बार आपको सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन लगता है?
अगर मुझे टॉप कंटेंडर्स के नाम लेने हों, तो रुबीना दिलाइक, करण वाही, ऋत्विक धनजानी और गौरव खन्ना। मैंने रुबीना के पुराने स्टंट देखे हैं और वह बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बाकी लोग भी मजबूत हैं, लेकिन उनके स्टंट मैंने ज्यादा नहीं देखे।

शो में दोस्ती किसके साथ होने वाली है?
मुझे लगता है मैं सबकी दोस्त बन जाऊंगी। मैं बहुत हैप्पी-गो-लकी इंसान हूं। मैं खुद पर भी जोक्स ले सकती हूं और दूसरों के भी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी से कोई दिक्कत होगी। शो में ओरी के साथ फन क्लिप्स बनाऊंगी और उनका सिग्नेचर पोज भी जरूर करूंगी।

जब पहली बार शो के लिए कॉल आया, तब आपका रिएक्शन क्या था?जवाबः मेरा पहला रिएक्शन था- 'फाइनली!' क्योंकि मैं सच में चाहती थी कि यह हो जाए। मैं खुद भी 'खतरों के खिलाड़ी' करना चाहती थी। जब कॉल आया, तब तक मैंने किसी को नहीं बताया था। जब सब फाइनल हो गया, तब घर जाकर मां को बताया। वो पहले शॉक हो गईं और बोलीं- 'तू कैसे करेगी खतरों?' फिर थोड़ा इमोशनल भी हो गईं क्योंकि मुझे लंबे समय के लिए बाहर जाना होगा।

मेंटली और फिजिकली खुद को कैसे तैयार कर रही हैं? मैं मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग हूं, लेकिन फिजिकली जहां मुझे लगता है कि थोड़ी कमी हो सकती है।, वहां मैं मेहनत कर रही हूं। मैं कैलिस्थेनिक्स कर रही हूं, जिम और स्विमिंग भी कर रही हूं। मुझे लगता है कि जहां फिजिकल स्ट्रेंथ कम होगी, वहां मैं मेंटल स्ट्रेंथ से उसे कवर कर लूंगी।

पहाड़ों की लड़कियां काफी मजबूत मानी जाती हैं। क्या उस टैग का प्रेशर है?इस बार सिर्फ दो पहाड़ी लड़कियां हैं- मैं और रुबीना। लोग पहाड़ों की लड़कियों को मेहनती और मजबूत मानते हैं।

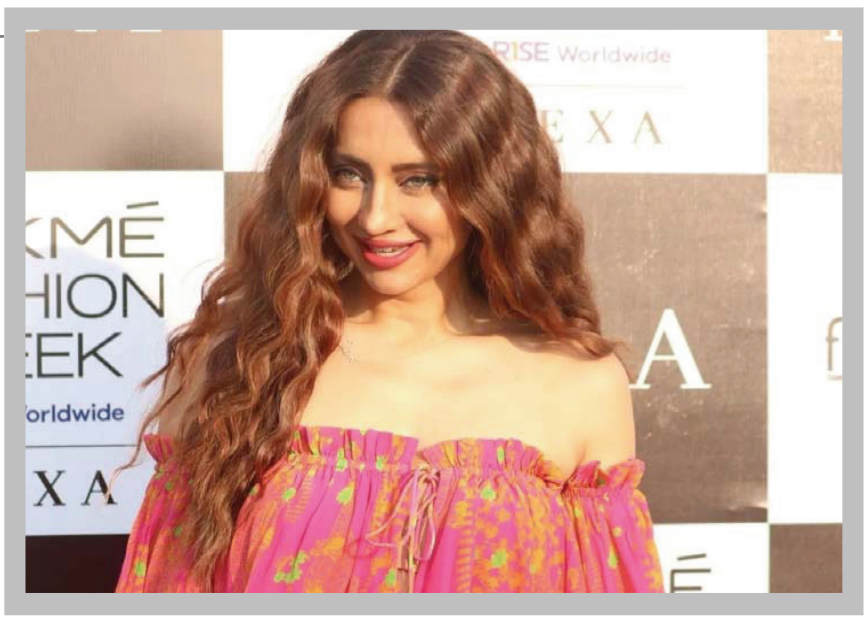

करण की एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा के क्रिप्टिक पोस्ट पर भड़के लोग

करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को दुबई में शादी के लिए प्रपोज किया। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर ने एक पोस्ट किया जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि अनुषा को जीवन में आग बढ़ने की जरूरत है। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के फैंस इस वक्त काफी खुश हैं क्योंकि करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को दुबई में शादी के लिए प्रपोज किया है। सोशल मीडिया पर करण और तेजस्वी के प्रपोजल के वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। करण और तेजस्वी के प्रपोजल की खबरों के बीच करण कुंद्रा की एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर ने एक क्रिप्टिक पोस्ट लिखा है, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं।**अनुषा ने किया क्रिप्टिक पोस्ट-**अनुषा दांडेकर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- मैं भगवान का शुक्रिया करती हूं। इसी के साथ उन्होंने लिखा अगर आपको पता है, तो आपको पता है। अनुषा का ये पोस्ट अब रेडिट पर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में अनुषा ने किसी का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन रेडिट यूजर्स इस पोस्ट को करण कुंद्रा के प्रपोजल से जोड़कर देख रहे हैं।**रेडिट पर वायरल हो रहा अनुषा का पोस्ट-**रेडिट पर जिस पेज से ये पोस्ट शेयर किया गया था, उसके साथ कैप्शन लिखा गया है- ये करण से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? लड़की, उस बात को 6-7 साल हो गए हैं और फिर भी तुम हर चीज करण के बारे में बना देती हो। सबसे मजेदार चीज तो ये है कि ये सबसे पहले करण के शोज देख लेती है, फिर अप्रत्यक्ष रूप से उनके बारे में बात करती है। करण के बाद इसकी कई रिलेशनशिप रही हैं, लेकिन फिर भी वो करण पर ही अटकी है। यहां क्लिक करके देखें रेडिट पोस्ट।इस रेडिट पोस्ट पर बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स के भी रिएक्शन आए हैं। एक यूजर ने लिखा- अनषा को आगे बढ़ने की जरूरत है। कभी तो आपको इस चीज से बाहर निकलना होगा। एक ने लिखा- किसी के स्पेशल दिन पर ये करना, आप काफी गलत हैं। एक ने लिखा- वो दोनों आपको नहीं पसंद हैं, ये मुझे पता है। पर किसी के खास दिन पर ये करना काफी घटिया हरकत है। एक ने लिखा- करण मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन ये आपको पोस्ट काफी अजीब है।करण कुंद्रा और अनुषा दांडेकर ने साल 2015 में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। 2016 से 2019 के बीच दोनों ने एमटीवी का शो लव स्कूल होस्ट किया था। हालांकि, लॉकडाउन में दोनों के ब्रेकअप की खबरें आईं। अनुषा ने करण पर चीटिंग का आरोप लगाया।करण और तेजस्वी की बात करें तो दोनों की मुलाकात बिग बॉस के घर में हुई थी। दोनों ने वहीं से एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। करण और तेजस्वी पिछले चार साल से साथ हैं। अब देसी ब्लिंग के आखिरी एपिसोड में देखने को मिला कि करण ने तेजस्वी को शादी के प्रपोज किया।

प्रोड्यूसर के पास नहीं थे पैसे... माधुरी दीक्षित को पहना दिए हीरो की पत्नी के कपड़े, ऐसे हुआ मेकअप

माधुरी दीक्षित के बारे में आप ये बात जानते हैं कि उन्हें एक प्रोड्यूसर ने पैसों की तंगी की वजह से लीड हीरो की पत्नी के कपड़े पहनाए थे। हीरो की पत्नी ने ही किया था मेकअप। पहचानिए इस फिल्म को। बॉलीवुड की धक धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित के सफल करियर के बारे में दुनिया बात करती है। बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई उनकी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उनके डांस सॉन्ग के चर्चे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं माधुरी के करियर की शुरुआत फ्लॉप फिल्मों से हुई थी। 1984 में आई पहली फिल्म अबोध के बाद एक्ट्रेस ने कई फ्लॉप फिल्मों में काम किया। उनमें से एक ऐसी भी फिल्म थी जिसमें माधुरी को हीरो की पत्नी के कपड़े पहनाए गए थे। फिल्म के प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं था।**शेखर और माधुरी की पहली मुलाकात-**शेखर सुमन ने अपने एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बताया। वो कहते हैं कि रेखा के साथ पहली फिल्म संसार के बाद उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई थी। प्रोड्यूसर सरवन सिंह रहल ने एक्टर को बताया कि एक नई लड़की आई है जिसका नाम माधुरी दीक्षित है। वो इस फिल्म की हीरोइन हैं। उस समय अपनी हीरोइन माधुरी से मिलने के लिए शेखर सुमन अपने प्रोड्यूसर के साथ माधुरी के घर पहुंचे। एक्टर ने कहा कि माधुरी उस समय नहाने गई थीं। जब वो आई तो उनकी खूबसूरती देखकर वो हैरान हो गए। माधुरी को देखते ही शेखर सुमन ने फिल्म के लिए हां कह दी थी।आगे शेखर सुमन ने बताया कि प्रोड्यूसर का बजट कम था। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि फिल्म की शूटिंग उनके घर पर की जाए। माधुरी के पास टैक्सी के पैसे नहीं थे इसलिए खुद शेखर सुमन अपने स्कूटर पर उन्हें हर सुबह उनके घर से लेने जाते, शूटिंग के बाद एक्ट्रेस को छोड़ने भी जाते थे। शेखर सुमन ने बताया कि प्रोड्यूसर के पास मेकअप आर्टिस्ट और आउटफिट के लिए भी पैसे नहीं थे। तो इस फिल्म के लिए उनकी पत्नी अल्का ही माधुरी का मेकअप किया करती थीं। और माधुरी ने फिल्म के कई सीन में अल्का के घर के कपड़े पहने थे। इस तरह और इतने स्ट्रगल देखने के बाद माधुरी ने सफलता की सीढ़ी चढ़ी है। शेखर सुमन और माधुरी दीक्षित ने जिस फिल्म में साथ काम किया था उसका नाम था मानव हत्या। ये फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी। फिल्म में शेखर सुमन, माधुरी दीक्षित के अलावा गुलशन ग्रोवर, अरविंद देशपांडे, शरत सक्सेना, राजेश पुरी, टॉम आल्टर, सुधीर दलवी, प्रवीण कुमार और सुनील थापा जैसे एक्टर्स थे। इस फिल्म का म्यूजिक अनु मलिक ने तैयार किया था।

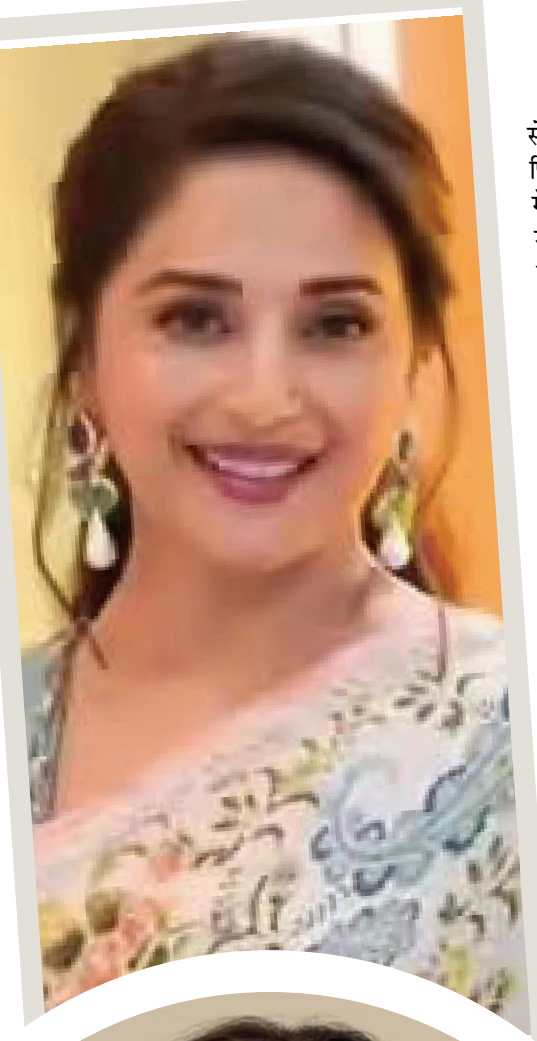

अंकिता लोखंडे को ऑफर हुई थी 2015 में आई ये हिट फिल्म, 7.4 है IMDb रेटिंग

अंकिता लोखंडे एक सफल टीवी एक्ट्रेस हैं। अपने करियर में अंकिता काफी टीवी शोज का हिस्सा रही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अंकिता लोखंडे ने साल 2015 में आई एक हिट फिल्म को रिजेक्ट किया था। आइए जानते कौन सी थी वो फिल्म? अंकिता लोखंडे टीवी की एक सफल एक्ट्रेस हैं। उन्होंने जी टीवी के शो पवित्र रिश्ता से अर्चना के रूप में घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी।

फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं अंकिता-अंकिता लोखंडे टीवी सीरियल्स के अलावा मणिकर्णिका और बागी 3 जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। पर क्या जानते हैं कि अंकिता लोखंडे ने अपने करियर में कई बड़ी फिल्मों को रिजेक्ट भी किया है।

2015 की हिट फिल्म को कर दिया था रिजेक्ट-आज हम आपको साल 2015 में रिलीज हुई एक ऐसी हिट फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे अंकिता लोखंडे ने रिजेक्ट किया था।

बदलापुर-हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है बदलापुर। बदलापुर में वरुण धवन लीड रोल में नजर आए थे।

अंकिता और वरुण धवन-वरुण धवन ने हाल ही में लाफ्टर शेफ्स के एक एपिसोड में बताया कि बदलापुर के लिए उन्होंने अंकिता लोखंडे से बात की थी। लेकिन अंकिता लोखंडे ने रिजेक्ट कर दिया था।

अंकिता ने क्यों रिजेक्ट की फिल्म-इसपर अंकिता लोखंडे ने कहा कि वो उस वक्त जो कर रही थीं, उसे लेकर वो काफी वफादार थीं। इस वजह से उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था।

2015 में रिलीज हुई फिल्म-बदलापुर की बात करें तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म 20 फरवरी 2015 को रिलीज हुई थी। **फिल्म का बजट और कमाई-** bo&officeindia.com के मुताबिक, फिल्म का बजट 29 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में 67.37 करोड़ की कमाई की थी।

श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट की है फिल्म-फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में वरुण धवन के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हुमा कुरैशी और यामी गौतम नजर आई थीं।

सलमान खान के गुस्से वाले वीडियो पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान का रिएक्शन, लिखा-यार सल्लू...

सलमान खान के गुस्से वाले वीडियो पर अब पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान का रिएक्शन सामने आया है। बीती रात सलमान ने हॉस्पिटल के बाहर खड़े पैपराजी पर शोर-शराबा मचाने के लिए चिलाया था। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो में सलमान को पैपराजी पर गुस्सा होते देखा जा सकता है। अब इस वीडियो पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने सलमान का गुस्से वाला वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। दरअसल, सलमान खान हिंदुजा हॉस्पिटल पहुंचते थे और जब वो बाहर आए तो पैपराजी उन्हें देखकर जोर से चिल्लाने लगे। हॉस्पिटल परिसर में इतना शोर सुनकर सलमान भड़क गए थे।**माहिरा खान ने किया रिएक्ट-**बीती रात सलमान खान अपने किसी खास से मिलने हिंदुजा हॉस्पिटल पहुंचे थे। यहां एक्टर को फॉलो करते हुए पैपराजी भी पहुंच गए। जब सलमान हॉस्पिटल से बाहर निकले तो एक्टर की एक झलक अपने कैमरे में कैद करने के लिए पैपराजी जोर से चिल्लाने लगे। हॉस्पिटल परिसर में इतना शोर सुनने के बाद सलमान खान का गुस्सा पैपराजी पर फूट पड़ा। उन्होंने इशारों में पूछा 'पागल हो? तुम्हारा कोई अपना यहां होता तो क्या तब भी ऐसा ही बर्ताव करते'। अब सलमान के इस अंदाज की तारीफ हो रही है। हॉस्पिटल के बाहर इस तरह का शोर-शराबा पाकिस्तान की एक्ट्रेस माहिरा खान को भी पसंद नहीं आया। उन्होंने सलमान खान के एक्शन की तारीफ करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सलमान के गुस्से वाले वीडियो पर रिएक्शन दिया है। माहिरा खान ने सलमान खान का गुस्से वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा 'यार सल्लू', इसके साथ उन्होंने इमोजी भी शेयर की है।

कमर्शियल बिल्डिंग्स में हादसों को रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला

सावधान ! बेसमेंट किचन और रूफटॉप रेस्टोरेंट्स का होगा सख्त सेफ्टी ऑडिट

बिना नोटिस होगी सीलिंग की कार्रवाई, लापरवाही बरतने वाले होटल और रेस्टोरेंट संचालकों पर गिरेगी गाज

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में लगातार सामने आ रही आगजनी की घटनाओं को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। स्वायत्त शासन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब पूरे राज्य के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का व्यापक स्तर पर फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल ऑडिट किया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को अब कोई ढील नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ सीधे जब्ती व सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकार का मुख्य फोकस विशेष रूप से बेसमेंट में चल रहे कमर्शियल किचन और रूफटॉप रेस्टोरेंट्स (छतों पर बने होटल व रेस्टोरेंट) पर रहेगा। हाल ही में हुए कई हादसों के विश्लेषण के बाद यह सामने आया है कि इन जगहों पर निकास के रास्ते बेहद संकरे होते हैं और गैस सिलेंडर या शॉर्ट सर्किट के कारण हादसे का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।

नए सरकारी आदेश से बढ़ेगी सख्ती -

24 घंटे एक्टिव रहेंगे कंट्रोल रूम : मानसून और संभावित हादसों को देखते हुए राज्य और जिला स्तर पर 15 जून से आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम 24 घंटे सातों दिन काम करेंगे।

सख्त इलेक्ट्रिकल ऑडिट : व्यावसायिक इमारतों में लगे ट्रांसफार्मर, वायरिंग, लोड कैपेसिटी और पैनल बोर्ड की जांच विद्युत विभाग के तकनीकी विंग द्वारा की जाएगी। पुरानी या जर्जर वायरिंग को तुरंत बदलने के निर्देश हैं।

फायर एनओसी अनिवार्य : सभी बहुमंजिला इमारतों, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और कोचिंग सेंटर्स के लिए वैध फायर एनओसी होना अनिवार्य है। जिन प्रतिष्ठानों की एनओसी समाप्त हो चुकी है, उन्हें तुरंत रिन्यू कराना होगा।

बेसमेंट और रूफटॉप पर पैनी नजर : बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों के बिना चल रहे बेसमेंट किचन को तुरंत बंद करने या शिफ्ट करने के निर्देश हैं। रूफटॉप रेस्टोरेंट्स में ज्वलनशील पदार्थों (जैसे फाइबर शीट्स या लकड़ी का अत्यधिक काम) के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

आम जनता और व्यापारियों के लिए जरूरी कदम -

व्यापारियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी इमारतों का तुरंत स्व-मूल्यांकन करवा लें। सुनिश्चित करें कि सभी फायर सिलेंडर रीफिल और चालू स्थिति में हों। बिजली के पैनल के पास कोई भी ज्वलनशील सामग्री न रखें। स्टाफ को आपातकालीन स्थिति से निपटने और फायर सिलेंडर चलाने की बेसिक ट्रेनिंग जरूर दें। यह नया अभियान जल्द ही सभी नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका) के स्तर पर शुरू होने जा रहा है, जिसमें स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीमों को भी शामिल किया जाएगा।

हादसों से सबक, अब जगी सरकार

दिल्ली के मालवीय नगर और जयपुर टोंक रोड जैसी हालिया आग की घटनाओं के बाद राजस्थान सरकार ने कमर कस ली है। राज्यभर में बेसमेंट किचन्स और रूफटॉप रेस्टोरेंट्स का कड़ा फायर व इलेक्ट्रिकल ऑडिट शुरू। बिना फायर हृहष्ट पाए जाने पर प्रतिष्ठान सीधे सील होंगे। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं!

लापरवाही पर होगी 'जीरो टॉलरेंस' की कार्रवाई

इस बार सरकार का रुख बेहद कड़ा है। यदि किसी प्रतिष्ठान में फायर फाइटिंग सिस्टम (जैसे स्प्रिंकलर, फायर एक्सटिंग्विशर, होज पाइप) खराब पाए जाते हैं, या आपातकालीन निकास द्वारों पर अतिक्रमण मिलता है, तो प्रशासन को बिना किसी पूर्व नोटिस के दुकान या बिल्डिंग को सील करने और भारी जुर्माना लगाने के अधिकार दिए गए हैं।

ग्रामीण सेवा शिविरों में मौके पर ही हो रहा है समस्याओं का समाधान

15 जून को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में होंगे शिविर

जयपुर

राज्य सरकार के निर्देशानुसार संचालित ग्रामीण सेवा शिविर-2026 के अंतर्गत 15 जून 2026 को जयपुर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा तथा पात्र व्यक्तियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि 15 जून को उपखण्ड सांगानेर की मोहनपुरा , जोबनेर की ढींढा, फागी की भोजपुरा, फुलेरा की लालाना, चाकसू की भोज्याड़ा और राडोली, सांभर की हबसपुरा, आमेर की बगवाड़ा, मौजमाबाद की उगरियावास, शाहपुरा की मामटोरी कला व शिवसिंहपुरा, चौमू की निवाणा व देवथला, माधोराजपुरा की डिडावता, बस्सी की टोडाभाटा व भूडला , जयपुर की निमेडा, जमवारामगढ़ की चावण्ड का मण्ड व माथासुला, दूदू की बिंगोलाव, किशनगढ़ रेनवाल की मुडोती, रामपुरा डाबडी की नांगल पुरोहितान ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर आमजन की परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण करेंगे। साथ ही राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पंचायती राज, कृषि, जलदाय, विद्युत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उन्होंने आमजन से अधिकाधिक संख्या में शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।

15 जून को जिलेभर में आयोजित होंगे शहरी सेवा शिविर–

शहरी नागरिकों को घर के नजदीक मिलेगा विभिन्न सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ, समस्याओं का होगा त्वरित समाधान

जयपुर

राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जयपुर जिले में 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक प्रातः 9.30 से सायं 6 बजे तक शहरी सेवा शिविर-2026 आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सेवाओं का मौके पर ही लाभ प्रदान किया जाएगा तथा लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि शहरी सेवा शिविरों में जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, साइनेज लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, मोबाइल टावर एनओसी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सहित विभिन्न सेवाओं से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पट्टों, उपविभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, लीज मुक्त प्रमाण पत्र सहित विभिन्न लंबित प्रकरणों का भी मौके पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविरों के दौरान शहरों में साफ-सफाई, सड़क मरम्मत, पैचवर्क, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, नालियों एवं सीवर लाइनों की मरम्मत, सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण तथा आवारा पशुओं को पकड़ने जैसी व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिविरों में विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं के आवेदन प्राप्त कर स्वीकृतियां जारी की जाएंगी। साथ ही पेंशन योजनाओं, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, पीएम स्वनिधि, जनधन, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य योजनाओं का लाभ भी पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कलक्टर ने बताया कि शिविरों में आमजन की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क, ई-मित्र सुविधा, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी, बैठने, पेयजल, बिजली एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। शिविरों के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है।

15 जून को यहां आयोजित होंगे शहरी सेवा शिविर–

15 जून को नगर पालिका बगरू के वार्ड 3 एवं 4, नगर पालिका बस्सी के वार्ड 3 एवं 4, नगर पालिका चाकसू के वार्ड 1 से 35, नगर परिषद चौमूं के वार्ड 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35 एवं 36, नगर पालिका दूदू के वार्ड 3 एवं 4, नगर पालिका जमवारामगढ़ के वार्ड 1 से 5, नगर पालिका जोबनेर के वार्ड 2, नगर पालिका कालाडेरा के वार्ड 2, नगर पालिका कानोता के वार्ड 2, नगर पालिका खेजरोली के वार्ड 3 एवं 4, नगर पालिका किशनगढ़-रेनवाल के वार्ड 15 एवं 16, नगर पालिका मनोहरपुर के वार्ड 3 एवं 4, नगर पालिका नरायना के वार्ड 3 एवं 4, नगर पालिका फागी के वार्ड 2, नगर पालिका फुलेरा के वार्ड 2 एवं 3, नगर पालिका सांभर लेक के वार्ड 22 एवं 23 तथा नगर परिषद शाहपुरा के वार्ड 12, 13, 31 एवं 33 में शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे।

जल संसाधन मंत्री ने केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का किया अवलोकन

जयपुर।

12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विषय पर आधारित तीन दिवसीय प्रदर्शनी का जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, धौलपुर में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराती है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की व्यापकता एवं प्रभावशीलता को समझने का अवसर प्रदान करती है। प्रदर्शनी के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि सरकार की विभिन्न योजनाओं ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं तथा राज्य सरकार की जनहितकारी पहल, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सुधारों तथा विकास परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की गई। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास, रोजगार संवर्धन तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से संबंधित उपलब्धियों को भी प्रमुखता से दर्शाया गया। उन्होंने प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन आमजन एवं प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करने तथा विकास यात्रा को समझने का प्रभावी माध्यम हैं। उल्लेखनीय है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी केंद्र एवं राज्य सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों तथा सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। प्रदर्शनी के माध्यम से नागरिकों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी, जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, गिर्राज सिंह, डॉ. शिवचरण कुशवाह, नीरजा शर्मा, मोतीलाल मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि व कर्मचारी उपस्थित रहे।

ग्रामीण सेवा शिविर में मौके पर ही काम सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों को किया डेलीगेट

खाली पद पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की पोस्टिंग कर सकेंगे संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टर

जयपुर

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों की समस्याओं, विशेषकर जमीन से जुड़े मामलों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। जनकल्याण शिविर के अन्तर्गत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 12 जून से 15 जुलाई तक 'ग्रामीण सेवा शिविर-2026' का वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टरों को मिले विशेष अधिकार इस महा-अभियान के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राजस्व विभाग ने प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। अभियान की अवधि के लिए समस्त संभागीय आयुक्तों और जिला कलक्टरों को विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है। इसके तहत वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में 'नॉन-फील्ड' (कार्यालयों/गैर-क्षेत्रीय पदों पर) कार्यरत तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को तुरंत प्रभाव से तहसीलों या उप-तहसीलों के रिक्त पदों पर पदस्थापित कर सकेंगे

राज्यभर में 12 जनवरी से शुरू हो रहे 'ग्रामीण सेवा शिविर-2026' अभियान में मौके पर ही समस्या समाधान के लिए राज्य सरकार ने कई अधिकारियों की शक्तियों को शिविर प्रभारियों व अन्य अधिकारियों को डेलीगेट कर दी है। ये आदेश 12 जून से 15 जुलाई तक प्रभावी होंगे।

शिविर प्रभारी आईएएस, आरएएस को मिली ये शक्तियां–

आदेशों के अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अंतर्गत आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित किये जाने एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अंतर्गत आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित किये जाने की जिला कलक्टर की शक्तियां 'ग्रामीण सेवा शिविर-2026' के लिये शिविर प्रभारी बनाए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दे दी गई हैं। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियां भी इन अधिकारियों को दी गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (अधिनियम सख्यां 3, वर्ष 1955) की धारा 251-ए व उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने के लिये उपखण्ड अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियां भी इन अधिकारियों को दी गई हैं। राजस्व अभिलेख की त्रुटियों के शुद्धिकरण के प्रकरणों के निस्तारण हेतु उपखण्ड अधिकारी की शक्तियां भी शिविर प्रभारी बनाए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दी गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संख्या 3, वर्ष 1955) की धारा 53 की उप-धारा (1) व (2) एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत भूमि के बंटवारे की तहसीलदार की शक्तियां 'ग्रामीण सेवा शिविर-2026' के लिये नियुक्त तहसीलदार/ नायब तहसीलदार को दी गई हैं।

कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार के 12 साल 'विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के' की थीम पर आयोजित प्रदर्शनी का किया अवलोकन

प्रदेश के चहुंमुखी विकास हेतु डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्धता से कर रही कार्य - जिला प्रभारी मंत्री

केंद्र एवं राज्य सरकार के ऐतिहासिक विकास कार्यों एवं योजनाओं की दी जानकारी

जयपुर।

अलवर जिले के प्रभारी मंत्री तथा कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीना ने रविवार को केंद्र सरकार के 12 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन तथा सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय अलवर के द्वारा नवीन सूचना केंद्र में 12 साल 'विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के' की थीम पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से प्रदान की।

सेल्फी पॉइंट पर ली सेल्फी, भपंग वादक पद्मश्री गफरुद्दीन खां मेवाती ने योजनाओं पर दी आकर्षक प्रस्तुति–

जिला प्रभारी मंत्री ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है, दुनिया में देश का मान-सम्मान बढ़ा है। इस दौरान भपंग वादक पद्मश्री गफरुद्दीन खां मेवाती के दल ने लोकगीत के माध्यम से सरकार की योजनाओं पर आकर्षक प्रस्तुति दी।

केंद्र एवं राज्य सरकार के ऐतिहासिक कार्यों की जानकारी –

डॉ. मीना ने प्रेसवार्ता में केंद्र सरकार के 12 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ नागरिकों को बहुआयामी गरीबी के जाल से सुरक्षित बाहर निकला गया, 4 करोड़ से अधिक पक्के पीएम आवासों का निर्माण करवाया, 81 करोड़ से अधिक लोगों को हर माह मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है, लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों का पौषण ट्रैक कर लाभांवित कराया गया, किसानों के बैंक खातों में 4.3 लाख करोड़ रूपये की सम्मान राशि का बिना किसी लीकेज के हस्तांतरण किया गया, करीब 2 करोड़ किसान और करीब 3 लाख व्यापारी ई-नाम पर पंजीकृत हुए, करीब 37 लाख घरों को पीएम सूर्यघर योजना से 78 हजार रूपये तक की सौलर सब्सिडी का लाभ प्रदान की गई, पीएम आवास योजना (शहरी) में लगभग 9 लाख करोड़ आवंटित कर करीब 1 करोड़ घर लोगों को दिये गए, 2.2 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुये, जिसमें 23 लाख से ज्यादा रोजगार मिले, 9 करोड़ से अधिक यात्रियों ने आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा की, 1155 किमी. में मेट्रो नेटवर्क विकसित किया गया, अब मैट्रो का 26 शहरों में विस्तार हुआ, 60 करोड़ नागरिकों को 5 लाख तक के सालाना मुफ्त इलाज की सुरक्षा दी जा रही है, इसके लिये देशभर के गांवो और कस्बों में 1.8 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का नेटवर्क स्थापित किया गया है, साथ ही अब 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी 5 लाख तक का मुफ्त उपचार प्रदान किया जा रहा है तथा 19 हजार से ज्यादा जन औषधि केन्द्रों का निर्माण किया गया।

उन्होंने कहा कि ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) मॉडल आधारित सशक्तिकरण हुआ है, हर घर नल का उपहार के तहत 16 करोड़ घरों में जल पहुंचा, 40 लाख करोड़ से अधिक का गारंटी फ्री मुद्रा लोन दिए गए जिन लाभार्थियों में से 75 प्रतिशत महिलाएं हैं, पीएम जनधन योजना से 32 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खाते खुले, 3 करोड़ से अधिक महिला किसान पीएम-किसान योजना से लाभान्वित हो रही है, 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बनी ग्रामीण भारत की नई पहचान, 2030 तक 3 करोड़ और नई लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, 3 करोड़ से अधिक महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं, देशभर में 2.2 लाख स्टार्टअप्स संचालित हैं, देश में 300 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स शुरू किए गए, 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स स्थापित किए गए, 10 हजार से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स 1.1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स को ट्रैनिंग दे रहे है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवंटित पक्के घरों में से 44.19 प्रतिशत घर एससी-एसटी समुदाय को दिये गये, 5 करोड़ आदिवासियों का जीवन बेहतर करने के लिए 79 हजार करोड़ से ज्यादा का धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान संचालित किया गया, दुनिया का सबसे उंचा चिनाब रेलवे ब्रिज, समुद्र पर बना अटल सेतु, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 1.46 लाख किलोमीटर से अधिक विस्तार, देश में 164 ऑपरेशनल एयरपोर्ट, देश में तेजी से 12 सेमीकण्डकर प्लांट आकार ले रहे है तथा दुनिया के 56 प्रतिशत डिजिटल लेनदेन अकेले भारत में हो रहे हैं, 51 लाख करोड़ से अधिक रूपये डीबीटी से सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए गए, सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन मिला, करीब 38,400 करोड़ का रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट के साथ ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन ब्रह्म, ऑपरेशन सागरबन्धु से लेकर वैक्सीन मैत्री तक भारत दुनिया का भरोसेमंद साथी बन रहा है तथा अयोध्या में 5 सदियों के लम्बे इन्तजार के बाद नव्य-भव्य-दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ है एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत आज पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है।

जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि पीएम कुसुम योजना(कम्पोनेंट-ए) अक्षय और सौर ऊर्जा स्थापना, पीएम कुसुम योजना (कम्पोनेंट-सी) सौरकृत फीडरों की संख्या के आधार पर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अन्तराष्ट्रीय योग दिवस पर 62 हजार 915 स्थलों पर 85 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेने पर, तम्बाकू नियंत्राण कार्यक्रम में उत्कर्ष कार्य, पोषण पखवाड़ा 2026 गतिविधियों, धरती आबा जन भागीदारी अभियान, खनिज ब्लॉकों की नीलामी में अनुकरणीय प्रदर्शन, स्वच्छता ही सेवा अभियान-2025 में लक्षित इकाइयों के रूपांतरण, वर्ष 2025 में अंगदान एवं प्रत्यारोपण में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान रहा। उन्होंने कहा कि राजस्थान को विकास की ऐतिहासिक सौगात के रूप में पंचपदरा में 79 हजार 459 करोड़ रूपये की लागत से 9 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता की रिफाइनरी एवं 13037 करोड़ रूपये की जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना की सौगात मिली। इसी प्रकार रामजल सेतु परियोजना प्रदेश की जल आवश्यकता को पूरा करने वाली ऐतिहासिक पहल है, जिससे 17 जिलों के लगभग 3.25 करोड़ लोगों को पेयजल एवं सिंचाई उपलब्ध होगी। यमुना जल समझौते के रूप में शेखावाटी के किसानों के लिए जल समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ। 35 हजार करोड़ रूपये से अधिक पीएम फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा वितरित किया गया।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक संपादक: नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, झोटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड़, जयपुर-302006 से मुद्रित एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झालाना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। प्रबंध संपादक- पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)